

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर राज0

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
प्रकरण संख्या- 370/2016(राजस्व वाद) दायर दिनांक - 15.7.2016

फैसल दिनांक - 10/9/2025

अनवान

- 1-श्री वालजी पिता रतना मीणा जाति भील उग्र बालिंग निवासी भीलूडा
- 2-श्री वजा पिता रतना मीणा जाति भील उग्र बालिंग निवासी भीलूडा
- 3-श्री रूपा पिता थाना मीणा जाति भील उग्र बालिंग निवासी भीलूडा
- 4-श्री रामा पिता थाना मीणा जाति भील उग्र बालिंग निवासी भीलूडा
- 5-श्री पेमा पिता थाना मीणा जाति भील निवासी भीलूडा के विधिक प्रतिनिधि -  
5/1- श्रीमती धूली बेवा पेमा मीणा  
5/2- श्री विरमल पिता पेमा मीणा  
5/3- श्री रामसन उर्फ रामचन्द्र मीणा
- 6-श्री धनजी पिता थाना मीणा जाति भील उग्र बालिंग निवासी भीलूडा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

- 1- श्री मानशंकर पिता दूर्गाशंकर जाति ब्राहमण उग्र व्यस्क निवासी भीलूडा।
- 2- श्री निरज पिता हरीशंकर भट्ट जाति ब्राहमण उग्र व्यस्क निवासी भीलूडा।
- 3- श्री वक्ता पिता मावा मीणा जाति भील निवासी भीलूडा
- 4- श्री हिरा पिता मावा मीणा, जाति भील निवासी भीलूडा तहसील सागवाडा
- 5- श्री भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण - श्री अशोककुमार कंसारा  
वकील प्रतिवादीगण- श्री मयंक दोसी  
निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 41,42,42(ख),88,188,209राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पीढीनामा के सअनुसार वादी संख्या 1 व 2 के दादा व वादी संख्या 3 से 65 के पिता स्व0 थाना पिता धूला व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता स्व0 मावा पिता धूला भीलूडा के रहने वाले थे। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 मूल धूला की संताने है तथा धूला की दो संताने हुई जिसमें स्व0 थाना व मावा



उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा  
जिला डूंगरपुर (गज)

उत्पन्न हुए। स्व० थाना की सन्तान रतना, रूपा, रामा, पेमा, धनजी तथा रतना फौत होने से वालजी व वजा रहे। स्व० गावा के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वारीस रहे। वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित स्व० थाना व मावा पिसरान धूला भील निवासी भीलूडा के स्वामित्व व कब्जेदारी के 15 खेत मोजा भीलूडा के संवत 2001 से 2010 की खतौनी में उनके नाम से दर्ज होकर उन खेतों का कुल रकबा 18 बीघा 17 बिरवा एवं खाता नम्बर 371 था।

यह कि वादीगण नम्बर 1 से 6 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के पिता थाना व मावा भाई होने से उक्त खसरे की आराजी में उस समय थाना व मावा दोनो भाईयों के बिच खेतों का आपसी बंटवारा हो गया था जिससे वादी नम्बर 1 से 6 के पिता थाना व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता मावा दोनो अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते रहे जिसमें थाना व उसके वारीस अपने हिस्से की आराजी खाता नम्बर 371 के खसरा नम्बर 664, 665, 666, व 667 पर काश्त करते आ रहे हैं।

सन् 2012 में पता चला कि उक्त खाते के खसरा नम्बर 664, 665, 666, 667 प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता दूर्गाशंकर के नाम से दर्ज है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 मिलकर प्रतिवादी नम्बर 1 के विरुद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का दावा उपखण्ड न्यायालय में पेश किया तथा उस दौरान वादीगण नम्बर 1 से 6 ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बाड माह जून सन 2015 में लगा रहे थे तब प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण के विरुद्ध 107-151 जा०फौ० की कार्यवाही की तथा साथ में एक दरस्तावेज बेचाननामा उक्त आराजीयात 664, 665, 666, 667 का सन 1956 का पेश कर वादीगण को उक्त खेतों से पुलिस मदद से बेदखल किया तथा दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हुआ।

वादीगण नम्बर 1 से 6 को उक्त रजिस्ट्री से ज्ञात हुआ कि थाना ने अपने हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री बेचान की वह बेचाननामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद का है तथा काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति ने सवर्ण को सन 1956 में बेचान का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम खूल चुका है।

यह कि काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ इसके बाद उक्त खसरे की रजिस्ट्री अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कर देने से उक्त सन 1956 में किया गया विक्रय अन्तरण शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होकर अवैध है तथा नामान्तरकरण प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता के बाद उसके वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में खूल चुका है वह भी अवैध व निरस्तनीय होकर शून्य है। यह कि उक्त विक्रय पत्र के बाद भी जो उल्लंघन हुआ उसकी विधि मान्य होने की घोषणा निहित सूय में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं



उपखण्ड अधिकारी  
सागवाड़ा  
जिला झुंगरपुर (राज.)

होने से उक्त विक्रय विलेख प्रतिवादी नंबर 1 के पिता दूर्गाशंकर के हक में किया गया शून्य व निष्प्रभावी है ।

यह कि आराजी संवत 2001 से 2010 की खतौनी में धूला के बाद उसके वारिस थाना व मावा के नाम संयुक्त खाता खूला तथा संवत 2022 के फर्द तुलनात्मक के खसरे का विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 8 व फर्द तुलनात्मक 2022 के बाद संवत 2029 में नये नम्बर रहे जो वाद पत्र की कलम संख्या 9 में वर्णित है। यह कि वादीगण नम्बर 1 से 6 के पिता व दादा थाना से सन 1958 में प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता दूर्गाशंकर ने तत्कालिन खसरा की उर्बाधा 17 बिस्वा आराजी कय कर ली जिसका फर्द तुलनात्मक वाद पत्र की कलम संख्या 8 व 9 में वर्णित है जिसके हाल खसरा नम्बर 1051,1052,1048,1068 की कुल 2 बीघा 14 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके पिता गैर अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने पर गलत तरीके से उनके खाते में दर्ज हो गई है।

यह कि उक्त खसरे में से प्रतिवादी नंबर 1 ने खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.14 बिस्वा जमीन प्रतिवादी नंबर 2 निरज को बेचान दिनांक 10.4.2013 को इजरिये रजिस्टर्ड बेनामा से कर दी वह भी अंतरण विलेख प्रतिवादी नंबर 1 का प्रतिवादी नंबर 2 के हक में किया गया वह वादीगण के विरुद्ध शून्य व निष्प्रभावी है । उक्त हस्तान्तरण शुरू से ही अवैध व शून्य होने से प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक नही होने से सन 1958 व 2013 में दोनों विक्रय विलेख व नामान्तरकरण शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त आराजीयात को प्रतिवादी बेचान कर देंगे या आवादी में संपरिवर्तन कर देंगे जिससे प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

वादीगण ने वाद के अन्त में बताया कि वादीगण वादग्रस्त जमीन पर काबिज थे, जून 2015 में प्रतिवादी नंबर 1 ने पुलिस मदद से वादीगण को बेदखल करने से प्रतिवादी कय शुदा जमीन अपनी बताने व उक्त हस्तान्तरण शुरू से ही शून्य व अवैध होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है, अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर 1051,1052,1048,1068 मोजा भीलूडा का हस्तान्तरण शून्य व निष्प्रभावी होने से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की उक्त आराजीयात का हस्तान्तरण व नामान्तरकरण शून्य घोषित किया जावे एवं वादीगण को वादग्रस्त जमीन का कब्जा दिलाया जाने , प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाने का निवेदन किया गया है।

वादी ने वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ दस्तावेज जमावन्दी, नक्षा ट्रेस, खतौनी आसामीवार, फर्द तुलनात्मक, दस्तावेज विक्रय पत्र, खतौनी बन्दोवस्त, दस्तावेज बेचान नामा निरज के हक में पेश किए गए है ।



उपखण्ड अधिकारी  
सागवाड़ा  
जिला जमिंदारी (राज.)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने समान जारी किए गए ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ओर से दिनांक 24.10.2016 को वकालात नामा पेश कर प्रतिवादी की ओर से जवाब हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना न्यायालय के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में उन्होंने कथन किया कि गांव भीलूडा के थाना व मावा दो भाई थे जिनके बीच में हुए बंटवारे में मौजा भीलूडा के खसरा नम्बर 664, 665, 666 व 667 की आराजी थाना के हिस्से में गई थी। जो थाना ने अपने हिस्से की आराजी को दिनांक 24.12.1949 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता दुर्गाशंकर पुत्र रूपरामजी ब्राहमण निवासी भीलूडा के पास रु. 250/- में गिरवी रखा था व इसके बाद उन्ही खेतों पर रु. 50/- पचास रु. ओर प्राप्त कर इन्हे कुल रु. 3,00/- तीन सौ रु. में दुर्गाशंकरजी को बाजाप्ता पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1956 के विक्रय किया था तभी से इन खेतों पर स्व. दुर्गाशंकरजी का व उनके बाद उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है। स्व. दुर्गाशंकरजी की कयशुदा भूमि को वक्त सेटलमेन्ट पूरी जाँच के बाद उनके हक में निष्पादित हुए विक्रय पत्र के आधार पर उनके खाते दर्ज की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने खाते की भूमि मेंसे कुछ भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय किया है एवं दिनांक 13.3.2014 को कुछ भूमि आबादी में भी संपरिवर्तित कराई है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। जिससे उन्हे इसे अपने खाते दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। समय के साथ जमीन की किमते बढ़ने से वादीगण की नियत खराब हो गई है एवं तब वे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के स्वामित्व एवं कब्जेदारी की भूमि हडपना चाहते हैं। इस कारण उनके द्वारा यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जावे।

पत्रावली में दिनांक 13.11.2017 को तनकीयात कायम कर घोषित की गई।

1-आया वादग्रस्त आराजीयात की रजिस्ट्री अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कर देने से उक्त सन् 1956 में किया गया विक्रय अन्तरण शुरू से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी होकर अवैध है तथा नामान्तकरण प्रतिवादी नं0 1 के पिता के बाद प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में खुल चुका है वह अवैध एवं निरस्तनीय होकर शुन्य है ?

(वादी)



उपखण्ड अधिकारी  
सागबाड़ा  
जिला झंझारपुर (यम.)

2-आया स्व0दुर्गाशंकर जी की कय शुदा भूमि को वक्त सेटलमेण्ट पुरी जांच के बाद उनके हक में निष्पादित हुए विकय पत्र के आधार पर उनके खाते दर्ज की गई थी ?

(प्रतिवादी)

3-दारदसी ?

वादीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह वालजी एवं धनजी ने साक्ष्य दी एवं दस्तावेज नक्शा ट्रेस EX1, खतोनी आसामीवार संवत् 2001 से 2010 तक फर्द तुलनात्मक संवत् 2022 EX 2, बन्दोबरस्त संवत् 2022 EX 3, बन्दोबरस्त संवत् 2027 EX 4, खतोनी जमाबन्दी 2022 EX 5, दस्तावेज बेचान नामा खेत नंग 3 मानशंकर ने निरज को बेचा EX 6, दुर्गाशंकर ने थाना से खरीदा उसकी रजिस्ट्री की नकल जमाबन्दी EX 7, जमाबन्दी संवत् 2069-2072 EX 8, नामान्तकरण नकल EX 9 प्रदर्शित कराये गये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 मानशंकर ने साक्ष्य दी एवं दस्तावेज दुर्गाशंकर के हक में किया गया रहन नामा प्रदर्श ए 1 उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए 1 ए, वादग्रस्त खेतों का दुर्गाशंकर के हक में किया गया विकय पत्र प्रदर्श ए 2 जिसकी छायाप्रति ए 2 ए, सेटलमेंट विभाग को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श ए 3 जिसकी छाया प्रति ए 3 ए, सेटलमेण्ट विभाग के पर्चे प्रदर्श ए 4 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श ए 4 ए, पर्चा लगान प्रदर्श ए 5 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श ए 5 ए, भूप्रबन्ध विभाग का पर्चा नोटिस प्रदर्श ए 6 जिसकी छायाप्रति ए 6 ए को प्रदर्शित कराये गये।

दौराने वाद वादी संख्या 5 की मृत्यु होने से उसके कायम मुकाम को वाद में उसके स्थान पर पक्षकार बनाया गया। वकील वादी द्वारा कायम मुकाम वारिसान का वकालात नामा एवं संशोधित अनवान पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 20.08.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर समायत की गई। वकील वादी ने बहस में बताया गया कि राज0टीनेन्सी एक्ट 1955 लागू होने के बाद 04.10.1956 में रजिस्ट्री की गई। विकय के बाद नामान्तकरण हो गया एवं जमीन अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को नहीं हो सकती है, दुर्गाशंकर व उसके बाद की रजिस्ट्रीयाँ खारिज की जावे एवं वाद का निर्णय वादी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया। वही वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बहस में कहा कि उक्त आराजी दिनांक 04.10.1956 को जरूर खरीदी गयी लेकिन यह पहले से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के पास गिरवी थी एवं उसी का विकय किया गया है। धारा 42 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान दिनांक 01.05.1964 से लागू हुए उसके पहले के विकय पत्र पर यह लागू नहीं होता है। इस कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। जब टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ



उपखण्ड अधिकारी  
हागवाड़ा  
जिला जयपुर (राज.)

उस वक्त यह धारा नहीं थी। जब इसमें पहला संशोधन हुआ तब अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को शून्यकरणीय घोषित करने का विकल्प दिया गया। इसके बाद जब पुनः वर्ष 1964 में संशोधन हुआ तो ऐसे विक्रय पत्र को शून्यकरणीय के स्थान पर प्रारम्भ से ही शून्य घोषित किया गया।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में निम्न कानूनी विनिश्चय प्रस्तुत किये -

1. Supreme court of india civil appeal no 6741-6742 of 2012 state of raj v/s anjane orgnic herbel pvt ltd
2. Ghanshayam and others v/s asha & anr appeal no 10 bharatpur decided 27 dec 2001.
3. High court gavshala sri karanpur v/s state &ors. S.B. civil writ petition no 1888 of 1995 decided on 27 nov 2000
4. State of rajasthan v/s kasha & ors. Appeal no 166/Udaipur of 97, decided on 3 september 2001.
5. State of rajasthan v/s dayaram reference no 87/ chiittorgarh oof 85 decided on 19 jan 1989.
6. Rodu & anr. v/s goriya & anr. -(171) revision no 120/s madhopur of 89 decided on 7<sup>th</sup> july 1994.

वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब के समर्थन में निम्न कानूनी विनिश्चय प्रस्तुत किये -

1. Sewalal v/s state of rajasthan D.B.C.W.P no 30 of 1976 decided on 09-05-1983
2. Jayprakash v/s board of revenue ajmer & ors. S.B civil writ petition no 3417 of 1997 decided on 18-09-2023.
3. Ramkaran (dead) though lrs. &ors. v/s state of rajasthan and ors. Civil appeal no 5853 of 2014(arising out of slp(c) no. 16638 of 2012) decided on 30-06-2014.
4. Banwarlal & ors. v/s logar & anr. Appeal/decree/ta/11499/2001/rajsamand, decided on 22-12-2011

तनकीयात पर निम्नानुसार निर्णय किया गया :-

1-आया वादग्रस्त आराजीयात की रजिस्ट्री अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कर देने से उक्त सन् 1956 में किया गया विक्रय अन्तरण शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होकर अवैध है तथा नामान्तकरण प्रतिवादी नं0 1 के पिता के बाद प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में खुल चुका है वह अवैध एवं निरस्तनीय होकर शून्य है ?

(वादी)



उपखण्ड अधिकारी  
राजस्थान  
जिला जूनागढ़ (राज.)

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। गवाह पी. डक्यू -1 बालजी ने अपनी जिरह में बताया कि मेरी उम्र 55 वर्ष की है, मेरे दादा थाना की मृत्यु 15-20 वर्ष हुए है किन-किन खेतों का विवाद है, उनका खसरा नं० मुझे याद नहीं है क्योंकि तीन बार नम्बर बदल चुके हैं। माया मेरे दादा थाना के भाई थे, मैं भीलुडा के रमणलाल पिता हरिलाल भट्ट को नहीं पहचानता था मैंने मानशंकर के पिता दुर्गाशंकर को देखा है उनकी मृत्यु कब हुई मुझे पता नहीं है। मैं मजदूरी व कृषि कार्य करता हूँ। मेरे खाते में दो बिघा सत्रह बिरवा जमीन है। दुर्गा शंकर जी ने जाल साजी कर रजिस्ट्री कराई गई है मानशंकर ने जब हम वादग्रस्त जमीन जब हम पर बाढ कर रहे थे तब पुलिस की मदद से हमको पकड़वाया व हमको पाबन्द कराया व स्वयं ने बाढ कर दी यह कहना सही है कि मानशंकर हमको वादग्रस्त खेतों पर नहीं जाने देता है इसलिए हमको यह दावा करना पडा दुर्गाशंकर ने वर्ष 1956 में थाना से रजिस्ट्री करवायी थी, अज खुद वहा मेरे दादा के रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर फर्जी है, विस्तृत बयान शामिल पत्रावली है तथा दिनांक 09.12.2019 को धनजी पिता थाना रौत निवासी भीलुडा के बयान कराये गये जो कि शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी मानशंकर के दिनांक 31.01.2022 को बयान लेखबद्ध किये गये। अपनी जिरह में प्रतिवादी मानशंकर ने वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद का विरोध करते हुए कहा गया कि उक्त आराजीयात उसके पिता के पास गिरवी थी जिसकी रजिस्ट्री उनके हक में दिनांक 04.10.1956 को नियमानुसार की गई हैं एवं खेतों पर मेरा ही कब्जा है। वादीगण अनाधिकृत रूप से उसकी जमीन को हडपना चाहते हैं। वकील पक्षकारान् के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कानूनी विनिश्चयों का विवेचन किया गया।

माननीय राज० उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय में यह माना है कि धारा 42 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के संशोधित प्रावधान जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के हक में निष्पादित विक्रय पत्र को प्रारम्भ से ही शुन्य घोषित किया गया है यह प्रावधान दिनांक 01.05.1964 से पूर्व के विक्रय पत्र पर लागु नहीं होता है। इस कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है।

इसके प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1956 पर धारा 42 बी के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। उक्त कानूनी विनिश्चय में परिपेक्ष में तनकी संख्या 1 विरुद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 निर्णित की जाती हैं।



उपखण्ड अधिकाारी  
 जयपुर  
 जिला जयपुर (पब.)

2-आया स्व0दुर्गाशंकर जी की कय शुदा भूमि को वक्त सेटलमेण्ट पुरी जांच के बाद उनके हक में निष्पादित हुए विक्रय पत्र के आधार पर उनके खाते दर्ज की गई थी ?

(प्रतिवादी)

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हुआ है एवं तनकी संख्या 1 व 2 दोनो एक दूसरे से सम्बंधित हैं। इस कारण तनकी संख्या 1 के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या 2 बहक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा सेटलेमेन्ट विभाग को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श ए 3 ए व दुर्गाशंकर के हक में निष्पादित विक्रय पत्र एवं सेटलमेन्ट के पर्चे आदि दस्तावेजो से भी इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। इस प्रकार से तनकी के निर्णय से यह न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल रहे हैं।

आदेश

तनकी संख्या 1 व 2 का वादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादीगण का यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण होने से खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा पृथक से मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान् अपना - अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 10/9/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार हो। नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर होवे।



(सुबोध सिंह चारण)  
उप-जुज आधिकारी  
सांगवान  
जिला सभागौरा

## डिगरी व मुकदमे इब्तादाई

(आ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

मुकाम - सागवाडा

बईजलास - श्री सुबोध सिंह चारण आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

370/2016 (वाद)

अनवान

1-श्री बालजी पिता रतना भीणा जाति भील उम बालिंग वगेराह-6 निवासी भीलुडा (वादीगण)

बनाम

1-श्री मानशंकर पिता दूर्गाशंकर जाति ब्राहमण उम व्यस्क वगेराह 4 निवासी भीलुडा।

2-तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण - श्री अशोककुमार कंसारा

वकील प्रतिवादीगण - श्री मयंक दोसी

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 41,42,42(ख),88,188,209

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कर्तई रुबरू श्री सुबोध सिंह चारण आर०ए०एस० मनिजजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादीगण का यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण होने से खारिज किया जाता है।

नीज .....मुबलिंग.....बाबत .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शीहर ..... फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक .....का अदा करे। बराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10 मास 09 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा  
जिला डूंगरपुर (राज.)

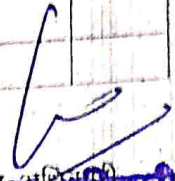
मुद्दई	रूपया	पै०	मुद्दायला	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		



उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा  
जिला डूंगरपुर (राज.)

बाबत ईजराय हुक्मनामा मीजान		बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	



  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सांगली  
 जिला दूंगरपुर (राज.)